

न्यायालयों में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पठानकोट की एक विशेष न्यायालय ने कठुआ मामले पर अपना फैसला सुनाया। यह नरिणय अपराध के अठारह महीने बाद दिया गया। यह अपेक्षाकृत एक त्वरित नरिणय था क्योंकि भारत में ज़्यादातर मामलों में पुलिस और न्यायापालिका दोनों स्तरों पर देरी के कारण उन्हें नसितारति करने में अधिक समय लगता है।

प्रमुख बडि

- भारत की अधीनस्थ अदालतों में ऐसे 31 मिलियन मामलों में से एक तहिई से अधिक मामले तीन वर्षों से लंबति हैं जनिमें अभी तक फरसट-पोर्ट-ऑफ-कॉल (first port-of-call) भी नहीं हुआ है। जबकि उच्च न्यायालयों में लंबति मामलों के संदर्भ में यह आँकड़ा और भी अधिक है, देश भर के सभी उच्च न्यायालयों में 8 मिलियन मामलों में से आधे मामले तीन साल से अधिक समय से लंबति हैं।
- वति मंत्रालय के वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक और वाणज्यिक मामलों का धीमी गति से नसितारण देश में नविश चक्र को पुनरजीवति करने वाले सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। हालाँकि सरकार द्वारा व्यापार और वाणज्य को आसान बनाने के लिये व्यापक रूप से प्रयास किये जा रहे हैं तथापि लंबति मामलों के चलते नविश पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब न्यायालयों में दर्ज मामले वर्षों तक लंबति रहते हैं, तो इसका समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान सरकार का अगला कदम व्यापार करने में आसानी से संबधति है जिसके अंतर्गत अपीलीय और न्यायिक क्षेत्र में लंबति मामलों का शीघ्र निपटान, सुनवाई में होने वाली देरी आदिको नसितारति करने पर बल देना है।
- इससे वविदों के समाधान और अनुबंध प्रवर्तन (Contract Enforcement) में बाधा उत्पन्न हो रही है, नविश के हतोत्साहति (Discouraging Investment) होने से परियोजनाओं का कार्य बाधति होता है, साथ ही कर संग्रह में भी बाधा उत्पन्न होती है, करदाताओं पर तनाव बढ़ता है और कानूनी लागत में इजाफा होता है।
- इसके लिये सरकार एवं न्यायापालिका में समन्वय स्थापति करने की आवश्यकता है जिससे कानूनी वलिंब (law Delay's) के कारणों की पहचान करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकें।
- समाचार पत्र द मटि (Mint) के सर्वेक्षण के अनुसार, यह एक देशव्यापी समस्या है, लेकिन देश के कुछ राज्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक खराब हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 50% से अधिक मामले बीते 3 वर्षों से लंबति पड़े हुए हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नचिली अदालतों में लंबति मामले का सीधा प्रभाव ऊपरी अदालतों पर पड़ता है एवं वहाँ भी मामले लंबति होने लगते हैं।
- कोलकाता तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय दोनों में संयुक्त रूप से 70% मामले तीन वर्षों से लंबति हैं। इसके विपरीत कुछ उच्च न्यायालय ऐसे भी हैं, जहाँ मामलों का नसितारण अधिक तेज़ी से होता है। उदाहरण के लिये, पंजाब और हरियाणा में 6% से भी कम लंबति मामले तीन साल से अधिक समय से लंबति हैं।
- कुल मलिाकर, देश के पूरवी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक मुकदमें लंबति पड़े हुए हैं।
- भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत लंबति मामलों के निपटारे की क्षमता, उसके पास उपलब्ध संसाधनों एवं लंबति मामलों की मात्रा और प्रक्रिया पर नरिभर करती है। वर्ष 2006 में भारत की नचिली अदालतों में 15 मिलियन मामले लंबति थे और वर्ष 2017 में यह आँकड़ा बढ़कर 20 मिलियन हो गया।
- वधिक शोधकर्त्ताओं के अनुसार, न्यायालयों में दाखलि होने वाले मामलों में वृद्धि देश के विकास का द्योतक होती है: यह न केवल एक समृद्ध समाज में अधिकारों के प्रतति अधिक जागरूकता को प्रकट करती है बल्कलोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालयों की ओर रुख करने के लिये भी प्रोत्साहति करती है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के उच्च न्यायालय भी रटि याचिकाओं (यह तब दायर की जाती है जब ऐसा प्रतीत हो कि भौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है) को स्वीकार करने में अत्यधिक उदार रवैया अपनाने लगे हैं इस व्यवहार के चलते 26% रटि याचिकाएँ ऐसी हैं जो पछिले पाँच सालों से अधिक समय से लंबति पड़ी हैं।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ तो लगातार बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप न्यायालय के संसाधनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 18 वर्षों में पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सभी पदों पर नयिकृति (31 न्यायाधीशों के साथ) पूर्ण हुई है। अन्य न्यायालयों में कालानुक्रमिक रूप से न्यायाधीशों की कमी बनी हुई है।
- भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या 1,049 है लेकिन वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या केवल 680 हैं अर्थात् लगभग 37% पद रक्ति है। इसी तरह नचिली अदालतों में भी न्यायाधीशों के 25% पद रक्ति पड़े हैं।

आगे की राह

- इसका स्पष्ट समाधान यह है कि अदालतों की स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि करते हुए और अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करना होगा। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने अनुमान व्यक्त किया था कि भारत में न्यायपालिकाओं में लंबित बैकलॉग मामलों को नसितारति करने के लिये 70,000 अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है।
- पछिले कई वर्षों में विभिन्न आयोगों ने इस मुद्दे से व्यापक रूप से नपिटने के लिये कई सफारिशें पेश की हैं। उदाहरण के लिये, वर्ष 2005 में 11वें वलित आयोग ने न्यायालयों में लंबित मामलों का तीव्रता से नसितारण करने के लिये फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की सफारिश की थी।
- हाल ही में वर्ष 2014 में 245वें वधि आयोग ने और अधिक छोटे मामलों (जैसे- यातायात अपराधों आदि) की सुनवाई के संदर्भ में हाल के कानून वशिषज्ओं द्वारा वशिष अदालतों की स्थापना किये जाने तथा नचिली अदालतों में न्यायाधीशों की सेवानवित्ता की आयु बढाने की सफारिश की।
- वर्ष 2018 में कानून मंत्री रवशिकर प्रसाद ने केंद्रीय न्यायकि सेवा आयोग की तर्ज पर नचिली अदालतों के लिये एक केंद्रीकृत भरती प्रणाली लागू करने का सुझाव दया था। इनमें से कुछ सफारिशों, जैसे- फास्ट-ट्रैक कोर्ट (कतुआ मामले में प्रयुक्त) को लागू भी कया गया, लेकिन अधिकतर सफारिशों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह देखते हुए कि न्यायालयों में लंबित मामले भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इस संदर्भ में जल्द-से-जल्द आवश्यक सुधार एवं प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: लाइव मटि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-next-generation-reforms-must-begin-in-courts>

